भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1358

14 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

चीनी मिलों में वित्तीय संकट

1358. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

श्री जगन्नाथ सरकार:

श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर की चीनी मिलों के गंभीर वित्तीय संकट से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो उक्त चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का चीनी मिलों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए गन्ने को जैव ईंधन के रूप से उपयोग करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): सामान्य चीनी मौसम में, चीनी का उत्पादन लगभग 320-360 लाख टन होता है जबकि घरेलू खपत 260 लाख टन है, जिसके परिणामस्वरूप चीनी मिलों में पुराना स्टॉक इकट्ठा हो जाता था। इस अधिशेष स्टॉक के कारण निधियां अवरूद्ध होती थी और चीनी मिलों की नकदी की स्थिति प्रभावित होती थी, परिणामस्वरूप गन्ना देय के भुगतान में विलम्ब होता था और अंततः गन्ना देयता का संचय होता था। अधिशेष चीनी की समस्या के निवारण के दीर्घावधि समाधान के लिए सरकार द्वारा अधिशेष गन्ने को इथेनॉल के उत्पादन की ओर परिवर्तित के लिए चीनी मिलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल के साथ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल के 20 प्रतिशत की ब्लेंडिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है। चीनी मौसम 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः लगभग 3.37 लाख टन, 9.26 लाख टन, 22 लाख टन और 36 लाख टन चीनी इथेनॉल में परिवर्तित की गई है। मौजूदा चीनी मौसम 2022-23 में लगभग 45 से 50 लाख टन की अधिशेष चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2025 तक, 60 लाख टन अधिशेष चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे चीनी की समस्या की लंबी सूची में सुधार, मिलों की नकदी में सुधार होगा, जिससे किसानों को गन्ना बकाया का समय से भुगतान में सहायता मिलेगी।

.....2/-

केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों की नकदी की स्थिति को सुधारने और किसानों को गन्ना देय बकाया का समय पर भुगतान करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए विभिन्न उपाय भी किए, जैसे चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान किया गया, बफर स्टॉकों के रखरखाव के लिए चीनी मिलों को सहायता दी गई, गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए बैंकों के माध्यम से चीनी मिलों को आसान ऋण दिलाया गया, चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित किया गया, आदि।

चीनी मौसम वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः लगभग 59.60 लाख टन, 70 लाख टन और 109 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और चीनी मौसम 2020-21 तक के 99 प्रतिशत से अधिक गन्ना देय एवं चीनी मौसम 2021-22 के 97.40 प्रतिशत गन्ना देय का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) और (घ): जी हां। चीनी क्षेत्र की सहायता करने के प्रयोजन से और गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, सरकार चीनी मिलों को अधिशेष गन्ने और चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने बी-हैवी शीरे, गन्ने के रस, शुगर सिरप और चीनी से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है और विभिन्न फीड स्टॉकों से उत्पादित इथेनॉल के लाभकारी मिल-द्वार मूल्य भी निर्धारित कर रही है। ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार चीनी मिलों और डिस्टिलरियों को उनकी डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित कर रही है जिसके लिए सरकार बैंकों से ऋण प्राप्त करने में उनकी मदद कर रही है जिसके लिए 6 प्रतिशत की दर से ब्याज छूट या बैंकों द्वारा लिए गए ब्याज का 50 प्रतिशत, इसमें जो भी कम हो, का वहन सरकार द्वारा किया जा रहा है। चूंकि चीनी की बिक्री में लगने वाले 3 से 15 माह के समय की तुलना में चीनी मिलों के खातों में चीनी मिलों/डिस्टिलरियों द्वारा इथेनॉल की बिक्री से सृजित राजस्व लगभग 3 सप्ताह के समय में ही जमा होता है, अतः इथेनॉल का उत्पादन चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करेगा और गन्ना किसानों के गन्ना बकाया का समय पर भुगतान करने में सहायक होगा।

विगत तीन इथेनॉल आपूर्ति वर्षों (दिसम्बर-नवम्बर) में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों को लगभग 48,573 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिससे चीनी मिलों/शीरा आधारित डिस्टिलरियों को किसानों को गन्ना देयताओं का समय पर भुगतान करने में सहायता मिली है।

******